

क्षेत्रीय नीतियों से आप क्या समझते हैं? अर्थ, परिभाषा तथा विभिन्न क्षेत्रीय नीतियों एवं उनके कार्यान्वयन को विस्तारपूर्वक समझाइए।

परिचय

भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। इन असमानताओं को कम करने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रीय नीतियाँ (Sectoral/Regional Policies) बनाई जाती हैं। इन नीतियों का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना है।

क्षेत्रीय नीति का अर्थ (Meaning of Sectoral Policy)

क्षेत्रीय नीति से आशय ऐसी नीति से है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र (Sector) जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, उद्योग, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण आदि के विकास के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

परिभाषा (Definition)

क्षेत्रीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र की समस्याओं के समाधान तथा उसके विकास के लिए पृथक योजनाएँ, कार्यक्रम एवं संसाधनों की व्यवस्था की जाती है।

क्षेत्रीय नीतियों की विशेषताएँ

1. प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग नीति बनाई जाती है।
2. क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
3. विशेषज्ञों द्वारा योजना तैयार की जाती है।
4. संसाधनों का क्षेत्रवार उपयोग किया जाता है।

5. विकास को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रीय नीतियाँ एवं उनका कार्यान्वयन

1. शिक्षा नीति (Education Policy)

उद्देश्य

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

साक्षरता बढ़ाना।

कौशल एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना।

कार्यान्वयन

विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना।

छात्रवृत्ति योजनाएँ।

शिक्षक प्रशिक्षण।

डिजिटल शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार।

2. स्वास्थ्य नीति (Health Policy)

उद्देश्य

सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार।

संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों की रोकथाम।

कार्यान्वयन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

टीकाकरण कार्यक्रम।

स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ।

पोषण एवं स्वच्छता कार्यक्रम।

3. कृषि नीति (Agricultural Policy)

उद्देश्य

किसानों की आय बढ़ाना।

कृषि उत्पादन में वृद्धि।

आधुनिक तकनीकों का उपयोग।

कार्यान्वयन

सिंचाई सुविधाओं का विकास।

उन्नत बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता।

कृषि ऋण एवं बीमा।

किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम।

4. रोजगार नीति (Employment Policy)

उद्देश्य

बेरोजगारी कम करना।

स्वरोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना।

कार्यान्वयन

रोजगार गारंटी कार्यक्रम।

कौशल विकास प्रशिक्षण।

स्वरोजगार योजनाएँ।

लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।

5. महिला एवं बाल विकास नीति

उद्देश्य

महिलाओं एवं बच्चों का संरक्षण एवं विकास।

पोषण एवं शिक्षा में सुधार।

महिला सशक्तिकरण।

कार्यान्वयन

आंगनवाड़ी सेवाएँ।

महिला सुरक्षा योजनाएँ।

पोषण कार्यक्रम।

बाल संरक्षण सेवाएँ।

6. सामाजिक सुरक्षा नीति

उद्देश्य

वृद्ध, दिव्यांग, विधवा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना।

कार्यान्वयन

सामाजिक पेंशन योजनाएँ।

आर्थिक सहायता।

बीमा योजनाएँ।

पुनर्वास कार्यक्रम।

7. पर्यावरण नीति (Environmental Policy)

उद्देश्य

पर्यावरण संरक्षण।

प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग।

प्रदूषण नियंत्रण।

कार्यान्वयन

वृक्षारोपण अभियान।

जल संरक्षण।

प्रदूषण नियंत्रण कानून।

पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम।

क्षेत्रीय नीतियों का महत्व

1. प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित विकास होता है।

2. संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होता है।
3. क्षेत्र विशेष की समस्याओं का समाधान होता है।
4. रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
5. सामाजिक न्याय एवं समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।
6. जीवन स्तर एवं मानव विकास में सुधार होता है।

क्षेत्रीय नीतियों की चुनौतियाँ

संसाधनों की कमी।

विभागों के बीच समन्वय का अभाव।

भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक विलंब।

योजनाओं का असमान क्रियान्वयन।

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं का सीमित पहुँचना।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय नीतियाँ किसी भी देश के समग्र विकास का महत्वपूर्ण आधार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं पर्यावरण जैसे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नीतियाँ बनाकर सरकार समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यदि इन नीतियों का पारदर्शी, प्रभावी एवं जनसहभागिता के साथ कार्यान्वयन किया जाए, तो सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा सतत विकास के लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ (References)

1. Friedlander, Walter A. (1977). Concepts and Methods of Social Work. Prentice Hall of India.
2. Titmuss, Richard M. (1974). Social Policy: An Introduction. George Allen & Unwin.
3. Kulkarni, P. D. (1979). Social Policy and Social Development in India. Association of Schools of Social Work in India.
4. Dubey, S. N. (2015). Social Work: An Integrated Approach. New Royal Book Company.
5. गोयल, एस. एल. एवं गोयल, राकेश. (2018). सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक नीति. आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।

6. सिंह, आर. बी. एस. (2016). समाज कार्य एवं सामाजिक नीति. रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।